EDITORIAL

Performance of BSNL

The performance of BSNL on financial and physical parameters has been in the arena of discussion since it becomes loss making. Hectic and continuous efforts have been taken by the various agencies including Trade Unions for the revival and better performance of BSNL. An internal core committee was formed during May 2011 to study and give detailed report. The committee has focused and recommended many valuable decisions.

Correcting and revitalizing our value chain-capacity constraints, laxity in maintenance, inadequate distribution, non-focused marketing and sales, apathy towards customer care were identified some of the areas that need attention. BSNL management addressed these problems with all commitment in the last 6 years and corrected the course to a large extent. Suggestions for the Improvement in fixed line where revenue potential declining year after year has been addressed like night free calling, Sunday free measures. The question of prepaid in fixed services is not felt seriously but unlimited calls bundled with data service is executed.

Suggestions like Device flexibility, simplified plans, improving customer interface are all implemented to a great extent. Organizational restructuring on the basis of Business verticals and rationalising staff to the business units are also almost done fairly. BSNL should report us back about the NGN architecture of consolidating 35000 exchanges and Offices into 100 Central Office Aggregation Units. We were told that NGN would be cost effective.

The other ideas suggested were 'separation of profitable Business from social obligation part' 'separation of infra part' and jobs of installation and commissioning only by BSNL staff. BSNL should report us back about the implementation of these ideas. Franchise, marketing, sales team, up gradation of Customer service centers are implemented in a better way.

Regarding manpower cost the suggestions were attractive VRS, outsourcing our technical expertise, sabbatical leave, option to become franchisee, performance assessment, rationalization of staff in top 25 cities, functional restructuring of small SSAs, reward for outstanding work and we do not know what is being cooked at Board room. Recommendations like Branding, e tendering, enterprise business are all implemented.

It was told to us that the expected result of implementing the entire recommendations would fetch revenue in CFA 45000 cr, CM 37000 cr, Enterprise 15000 cr and New Business 4600 cr and thereby our business would touch one lakh crore. We do not know what happened to these expectations and where the lacunae lie. Unfortunately our great edifice started heading to losses since 2009-10 onwards. The year wise losses since that period up to 2014-15 stated in the financial statements are 1823 cr, 6384 cr 8851, 7884, 7019, 8324cr.

Regarding the year 15-16 the company loss Rs. 8324 is somewhat heightened loss due to amendment in companies act 2013 and if calculated without taking the provisions of 2013 amendment, the loss would be 5370 cr. BSNL revenue as per TRAI report for FY 2016-17 is 28018 cr where as the total revenue of telecom industry is 2.74 lakh crores. Our revenue increased 0.45 % comparing last year.

The Committee of public sector Undertaking through LS secretariat has questioned the wisdom of forming separate tower corporation to improve the financial condition of BSNL . The BSNL management has rightly rejected the recommendations of BRPSE regarding merger of ITI and MTNL with BSNL and recently MOC has also stated that there is no proposal as on date the merger of MTNL though the unions of MTNL are agitating for the merger.

To the report of Committee for Public sector Undertakings the reasons stated for losses in BSNL are

a. Uneconomical landline business inherited from DOT, unviable rural wireline

b. Legacy of huge manpower from DOT and increase of cost on wages

c. Procedural requirements and time lags giving edge to Private Telcos,

d. Under utilisation of equipped capacity and procedural wrangles for further expansion

The COPU questioned the responsibility of DOT by asking 'is it not the responsibility of DOT to identify problems beyond the control of BSNL and provide possible solutions' . The parliamentary Committee also concluded that the performance review meetings of DOT have been ineffective and the DOT has failed in its responsibility of ensuring desired level of performance of BSNL.

The PRCs set up by GOI for the Executives of PSUs have been linking pay revision with Profits and restricting the same with 20 % dip of PBT in the name of affordability clause. This time in 3rd PRC a serious paradigm shift in defining affordability and completely synchronizing with profitability is exercised that is the state of yielding future profit is now matched presently with ability to be afforded. Thro Sathish Chandra 3rd PRC, the GOI is telling point blank that the workers of PSUs are eligible to any pay revision that after 10 years only if they show and earn profit to the concerned PSUs. Neither the management nor the ministry concerned are taking any blame or responsibility for the sordid affairs of the particular PSU. The entire blame is squarely on workers and they become victims of the neo-liberal economic system.

Let all the Unions and associations sit together and dispassionately understand the situation and design our future course of actions. Even one step with all is the surest way and help us move together. NFTE BSNL has been doing and will do its best to use all means available to bring pay revision by forging unity of all forces. Let us hope for the better by echoing in one voice.

संपादकीय

बीएसएनएल का प्रदर्शन

बीएसएनएल की आर्थिक हानि को देखते हुए उसकी वित्तीय और भौतिक मापदंडों पर चर्चा हो रही है। बीएसएनएल के पुनरूद्धार और बेहतर प्रदर्शन के लिए ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न संस्था द्वारा निरतंर प्रयास किये गए है। इसका अध्ययन समीक्षा करने के लिए आंतरिक समिति का गठन मई 2011 में किया गया था और यह समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की सिफारिश की है।

हमारे श्रृंखला को सुधारना और पुनजीवित करना; क्षमता की कमी; उपकरणों के रखरखाव में ठिलाई, अपर्याप्त वितरण और मार्केटिंग, बिक्री सेवा और ग्रहक के प्रति उदासीनता कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बीएसएनएल प्रबंधन ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ पिछले छह वर्षों में इन समस्याओं को समाधान किया और काफी हद तक सही किया। जहां साल–दर साल से फिक्स्ड लाईन के राजस्व में लगातार गिरावट आ रही थी वहां रात में मुफ्त बातें और रविवार को नि:शुल्क सेवा जैसे उपाय अमल में लाये। फिक्स्ड सर्विस में प्रीपेड से गंभीरता से नहीं ली गयी लेकिन डेटा सेवा के साथ सम्मिलित असमिति कॉल को जोड़ा गया।

सरलीकृत योजनाएं तथा ग्राहकों के साथ अच्छा बर्ताव जैसे सुझाव जैसी योजनाएं काफी हद तक लागू की गयी। बिजनेस वर्टिकल और कर्मचारियों का व्यावसायिक इकाइयों के लिए संगठनात्मक पुर्नगठन पर्याप्त रूप से किया गया। बीएसएनएल को हमें बताना होगा कि एम.जी.एन माध्यम से कैसे 3500 टेलीफोन केंद्र और कार्यालय 100 केंद्रीय कार्यालय में लायी जायेगी। हमे बताया गया था कि एन.जी. एन प्रभावी होगा। लाभदायक व्यापार को सामाजिक दायित्व से अलग करना और बुनियादी ढ़ांचे को अलग करते हुए इंस्टालेशन और उसे प्रवर्तन में लाने का काम ही बीएसएनएल के कर्मचारियों का होगा। फ्रैंचाइज, विपणन, बिक्री टीम और ग्राहक सेवा केन्द्रों का उन्नयन बेहतर तरीके से किया गया।

मैन पावर का खर्चे (लागत) के बारे में स्वेच्छानिवृत्ति, हमारी तकनीकी विशेषता को आउटसोर्सिंग, अध्ययन अवकाश, कर्मचारियों फ्रैंचाइजी बनने का विकल्प वार्षिक मुल्यांकन, उत्कृष्ट कार्य के लिए इनाम और 25 श्हारों में कर्मचरियों का तर्क संगत उपयोग करते हुए, छोटे एस.एस. एम का कार्यात्मक पुनर्गठन लेकिन हम यह नहीं जानते कि बोर्ड रूम में क्या हुआ है बांडिग, ई निविदायें और एंटरप्राइज बिजनेस जैसी सभी सुझाव लागू किये गये।

हमें बताया गया था कि पूरे सिफारिशों को लागू करने का अनुमानित परिणाम सीएफए 4500 करोड़ सीएम 3700 करोड़ एंटरप्राईज 15000 करोड़ और नई बिजनेस 4600 करोड़ रूपये में राजस्व प्राप्त होगा और इससे हमारा कारोबार करीबन एक लाख करोड़ तक पहुंच जायेगा। हमें नहीं पता कि इन उम्मीदों के साथ क्या हुआ और हमारा बीएसएनएल 2009–10 के बाद से घाटे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।

वित्तीय विवरणों में कहा गया कि 2014–15 तक की अवधि के अनुसार सालाना हानि 1823 करोड़, 6384 करोड़, 8851 करोड़, 7884 करोड़, 7019 करोड़, और 8324 करोड़ है। साल 15–16 के संबंध में कंपनी को 8324 करोड़ का नुकसान हुआ है।

साल 15–16 के संबंध में कंपनी का 8324 करोड़ का नुकसान हुआ है। 2013 में संशोधन किये बिना गणना की गई है तो नुकसान 5370 करोड़ होगा। वित्त वर्ष 2016–17 के लिए ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल का राजस्व 28018 करोड़ है क्योंकि दूरसंचार उद्योग का कुलराजस्व 2.74 लाख करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना हमारे राजस्व में 0.451 की वृद्धि हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र समिति ने लोक सभा सचिवालय द्वारा बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति सुधार लाने के लिए अलग टॉवर कंपनी बनाने के विचार पर सवाल उठाया। बीएसएनएल प्रबंधन में बीएसएनएल के साथ आइटीआइ और एमटीएनएल का विलय संबंध में बीआरपीएसई की सिफारिशों को सही तरीके से खारिज कर दिया और हाल ही में एमओसी ने भी कहा है कि एमटीएनएल के विलय का प्रस्ताव नहीं है हालोंकि एमटीएनएल के युनियन विलय के लिए आंदोलन कर रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए समिति की रिपोर्ट के

लिए बीएसएनएल में नुकसान के लिए कारण बताए गए हैं:

(1) आर्थिक रूप से नुकसान देने वाली लैंडलाइन का कारोबार एवं अजीवित ग्रामीण लाइनों का रखरखाव डीओटी से हस्तांतरित हुआ।

(2) डीओटी से भारी कर्मचारियों की संख्या मिली जिससे वेतन भत्तों का खर्च बढ़ा।

(3) काम करने के ढीले पुराने तरीकों से निजी कंपनियों को जगह लेने में आसानी हुई।

(4) उपकरणों के क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं होना और आगे के विकास में रूकावट पैदा करना।

सार्वजनिक उपक्रम समिति ने डीओटी की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए सवाल कैरियर की बीएसएनएल के नियंत्रण से परे समस्याओं की पहचान करने और समाधान प्रदान करने के लिए डीओटी की जिम्मेदारी नहीं है? संसदीय समिति ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि डीओटी की प्रदर्शन समीक्षा बैठक अप्रभावी रही है और डीओटी बीएसएनएल के प्रदर्शन के वांछित स्तर को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी में विफल रही है।

पीएसयू के कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पीआरसी वेतन संशोधन को मुनाफे और पीबीटी को आर्थिक क्षमता के साथ जोड़ रही है।

इस वक्त तीसरे वेतन संशोधन समिति ने आर्थिक क्षमता को परिभाषित करने में गंभीर बदलाव करते हुए भविष्य में होने वाले मुनाफे को आज के आर्थिक समता को जोड़ा है। सतीश चंद्र समिति के माध्यम से भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पीएसयू के मजदूरों को अगले 10 साल के बाद का वेतन संशोधन के लिए पात्र होंगे जबकि वह पीएसयू साथ में होगा। संबंधित पीएसयु के संबंधित मामलों के लिए संबंधित प्रबंधन और न ही मंत्रालय, कोई भी दोष या जिम्मेदारी लेने से मुकर रहे हैं। सूपर्ण दोष मजदूरों पर डाल रहे हैं और मजदूर नवउदार आर्थिक प्रणाली के शिकार बन रहे हैं।

सभी यूनियनों और संघों को एक साथ बैठकें प्रचलित परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई सोचनी चाहिए। एक कदम सभी के साथ चलना ही निश्चित रूप से हमें एक साथ चलने में सहायता करता है। हम वेतन संशोधन लाने के लिए सब संगइनों की एकता लाने के लिए हरतरह की कोशिश और साधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमें एकजुट होकर बेहतर आशा की उम्मीद करें।